



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.) ⑦

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण

निम्न - 2784-8116

२३

श्री राहुल निपट आदि
द्वारा उज्जैन केम्प पर
प्रस्तुत
12-8-16

Hiral
24/8/16

Om
12/8/16

- 1- गंगाधर पिता श्री हमीरसिंहजी,
- 2- बापूलाल पिता श्री कुंवरजी,
- 3- केशरसिंह पिता श्री कुंवरजी,
- 4- मोहनलाल पिता श्री कुंवरजी,
- 5- कृष्णाबाई पिता श्री कुंवरजी,
- 6- पिंगलबाई पिता श्री कुंवरजी,
- 7- पूरणसिंह पिता श्री गंगाधरजी
- 8- प्रेमबाई पिता श्री कुंवरजी,
- 9- हुकुमसिंह पिता श्री बापूलालजी
- 10- जगदीश पिता श्री बापूलालजी,
- 11- रूपसिंह पिता श्री जगन्नाथजी,
- 12- ज्ञानसिंह पिता श्री जगन्नाथजी,
- 13- ममताबाई पिता श्री जगन्नाथजी,
- 14- ललताबाई पिता श्री जगन्नाथजी,
- 15- अवन्तिबाई पिता श्री जगन्नाथजी,
- 16- राजेश पिता श्री केशरसिंहजी,
- 17- पंकज पिता श्री केशरसिंहजी,
- 18- नितेश पिता श्री केशरसिंहजी,
- 19- देवराज पिता श्री मोहनलालजी,
- 20- राहुल पिता श्री हुकुमसिंहजी,
- 21- कपिल पिता श्री जगदीशजी, समस्त
निवासीगण-ग्राम भादाहेड़ी तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- जोरावरसिंह पिता श्री दरियावसिंहजी,
- 2- रेशमबाई पति श्री जोरावरसिंहजी,

निरंतर...2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



-2-

- 3- शिवनारायण पिता श्री जोरावरसिंहजी,
निवासीगण-ग्राम भादाहेड़ी तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)
4- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
महोदय, जिला शाजापुर (म.प्र.)

—अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय संभाग आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रार्थीगण
के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 म.प्र. भू-राजस्व संहिता को निरस्त किये
जाने के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2784-पीबीआर/16

जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक

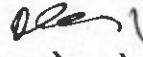
कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारी एवं अभिभाषक
आदि के हस्ताक्षर

6-12-2016

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त के जिस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । स्थगन देना अथवा नहीं देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर है, और उनके द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप स्थगन के संबंध में निर्णय लिया जाता है । अतः आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष